हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

अश्वनी कुमार एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 6015/2009)

नवंबर 26, 2015

(एम.वाई.इकबाल और सी. नागाप्पन, न्यायमूर्तिगण)

हिमाचल प्रदेश भूमिधारण अधिकतम सीमा अधिनियम, 1972: धारा 4- अनुमत क्षेत्र- की गणना- अभिनिर्धारित: जहां कोई व्यक्ति परिवार का एक सदस्य है, अनुमत क्षेत्र की गणना करने में उस व्यक्ति द्वारा धारित भूमि का परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि को जोड़ा जायेगा। एक वयस्क पुत्र को पृथक इकाई माना जायेगा और उसे पृथक इकाई के रूप में परिवार के लिए अनुमत क्षेत्र तक की सीमा तक अनुमत क्षेत्र रखने का अधिकार है इस शर्त के साथ कि परिवार की एवं उस पृथक इकाई की संयुक्त भूमि को साथ रखने पर अनुमत क्षेत्र के दुगुने से अधिक नहीं होगी।

न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया:

धारा 4 की सरल भाषा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी एक परिवार हो सकता है, जो संपत्ति रखने में सक्षम हो, जिसमें पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चे शामिल हों। धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों वाले परिवार का अनुमेय क्षेत्र उसमें दी गई सीमा तक होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4(1) के तहत, परिवार नाबालिग बच्चों की संख्या के संदर्भ में सीमित है, हालांकि परिभाषा खंड में, यानी धारा 3(ई) के तहत, "परिवार" नाबालिग

बच्चो तक सीमित नहीं है। इसलिए, इस अधिनियम के तहत अनुमत क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से परिवार को एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में लिया जाएगा। हालाँकि, धारा 4 की उपधारा (4) यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई माना जाएगा और वह उपधारा (1) और (2) के तहत एक परिवार के लिए स्वीकार्य सीमा तक भूमि का हकदार होगा। इस शर्त के अधीन कि परिवार की कुल भूमि और अलग-अलग इकाइयों की कुल भूमि उक्त उप-धारा के तहत अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगी। धारा 4 की उपधारा (6) यह स्पष्ट करती है कि जहां कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि को इस उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा। अनुमेय क्षेत्र की गणना करने में। यह प्रावधान अपने स्पष्ट शब्दों में किसी व्यक्ति के वयस्क पुत्र के मामले में एक प्रकार का अपवाद प्रदान करता है। उस स्थिति में ऐसे वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा और वह परिवार के अनुमेय क्षेत्र की सीमा तक अनुमेय क्षेत्र की अलग इकाई पाने का हकदार है, बशर्ते कि परिवार की कुल भूमि और एक की कुल भूमि अलग-अलग इकाइयों को एक साथ रखने पर अनुमेय क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम उपधारा (4) को सूक्ष्मता से पढ़ें तो पता चलता है कि पहले भाग में विधायिका ने "पृथक इकाई" शब्द का प्रयोग किया है लेकिन बाद के भाग में विधायिका ने "पृथक इकाईयां" शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। धारा 4 की उप-धारा (4) के शुरुआती शब्द, "एक व्यक्ति के प्रत्येक वयस्क पुत्र" से शुरू होते हैं, जिसका अर्थ है कि भले ही किसी व्यक्ति के एक से अधिक वयस्क पुत्र हों, सभी को अलग-अलग इकाई के रूप में माना जाएगा, लेकिन इस शर्त के अधीन कि परिवार की कुल भूमि और अलग-अलग इकाइयों की कुल भूमि उक्त उप-धारा के तहत अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगी। (पैराज 13, 14) (151-एच; 152-ए-एच;) (153-ए-बी)

गजनान और अन्य बनाम सेठ बृंदाबन 1971 (1) एससीआर 657: (1970) 2 एससीसी 360; राज नारायण पांडे और अन्य बनाम संत प्रसाद तिवारी और अन्य 1973 (2) एससीआर 835: (1973) 2 एससीसी 35; इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, आदि एआईआर (1993) एससी 477: 1992 (2) पूरक एससीआर 454- के द्वारा।

राजकुमार राजिन्द्र सिंह बनाम भारत संघ, आईएलआर 1976 एचपी 453- अस्वीकृत।

केस कानून संदर्भ

1971 (1) एससीआर 657	द्वारा संदर्भित	पैरा 14
1973 (2) एससीआर 835	द्वारा संदर्भित	पैरा 14
आईएलआर 1976 एचपी 453	अस्वीकृत	पैरा 18
1992 (2) पूरक एससीआर 454	द्वारा संदर्भित	पैरा 21

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील सं. 6015/2009

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला के सी.डब्ल्यू.पी. नं. 180/1992 में दिनांकित 07.05.2007 के निर्णय और आदेश से।

अपीलार्थीगण की ओर से सुर्यनारायण सिंह (प्रगति नीखरा के लिए)।

प्रतिवादीगण की ओर से अनीप सचथे, मोहितपाल, शगुनमटटा, अनिलनाग।

न्यायालय का निर्णय एम. वाई. इकबाल, जे. द्वारा दिया गया था।

1. यह अपील विशेष अनुमति द्वारा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 7.5.2007 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की और राजस्व

अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया गया था, यह मानते हुए कि एक देव राज के परिवार का प्रत्येक जमींदार एक अलग इकाई का हकदार था।

2. संक्षेप में तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं के पूर्ववर्ती देव राज के पास गांव कलरूही और मुबारिकपुर में 2400 कनाल 9 मरला भूमि मालिक के रूप में थी। उसे फॉर्म सी-वी में नोटिस जारी किया गया था जिसमें 1767 कनाल 9 मरला क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट, 1972 के तहत अधिशेष घोषित करने का प्रस्ताव था। आपत्ति दर्ज करने के बजाय, भूमि मालिक ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाये। 22.7.1976 को, ऊना जिले के कलेक्टर ने एक आदेश पारित किया कि स्वर्गीय देव राज की पत्नी श्रीमती कला देवी के स्वामित्व वाली भूमि और देव राज के पुत्रों यश पाल, धर्म पाल, राम पाल को भूमि स्वामी देव राज की जोत से बाहर रखा जाए और भूमि धारण करने वाले परिवार के सभी सदस्यों को निर्धारित अनुमेय क्षेत्र की सीमा तक उस पर अधिकार प्राप्त रहेगा। इसके बाद, पुनरीक्षण में संदर्भ पर निर्णय लेते हुए, वित्तीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश ने उत्तरदाताओं को उचित अवसर देने के बाद मामले को कानून के अनुसार नए सिरे से निर्णय के लिए कलेक्टर को भेज दिया। प्रतिप्रेषण के बाद, कलेक्टर लैंड सीलिंग, ऊना ने आदेश पारित किया कि देव राज और उसके परिवार के राम पॉल के साथ नियत दिन यानी 24.1.1971 को वयस्क पुत्र होने के कारण, भूमि मालिक अनुमेय क्षेत्र के रूप में भूमि की दो इकाइयों का हकदार है।

3. उपरोक्त आदेश के खिलाफ अपील में, मंडलायुक्त, कांगड़ा डिवीजन ने 30.3.1986 को माना कि धारा 4(6) के प्रावधान बहुत स्पष्ट हैं जिसके तहत परिवार के सदस्यों द्वारा रखी गई कुल भूमि पर विचार किया जाना चाहिए। पुनरीक्षण में वित्तीय आयुक्त (अपील) ने मंडलायुक्त के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद, देव

राज के उत्तराधिकारी ने राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देते हुए हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की।

4. उच्च न्यायालय के समक्ष, उत्तरदाताओं ने दलील दी कि रिट याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत नियत दिन से पहले अपने आप में व्यक्तिगत भूमि मालिक हैं। अधिनियम की धारा 4 के तहत अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए उनकी व्यक्तिगत भूमि जोत को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता है और ऐसे याचिकाकर्ता अधिनियम के तहत व्यक्तिगत रूप से एक इकाई के हकदार हैं। रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 को छोड़कर सभी याचिकाकर्ताओं की व्यक्तिगत हिस्सेदारी अनुमेय क्षेत्र से काफी नीचे है। इसलिए, उनके अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करते समय, केवल रिट याचिकाकर्ता नंबर 1 की भूमि के अधिशेष क्षेत्र को बाहर रखा जाना चाहिए, अन्य के पास कोई अधिशेष क्षेत्र नहीं है क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जोत अधिनियम की अनुमेय सीमा के भीतर है। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 22.7.1976 को पारित आदेश लेकिन उस आदेश के बाद पारित अन्य आदेश अधिनियम के अनुसार नहीं हैं। यह आग्रह किया गया है कि धारा 4 की उपधारा (4) में एक जमींदार का वयस्क पुत्र उपधारा (1) और (2) के तहत एक 'परिवार' के लिए स्वीकार्य सीमा तक एक अलग इकाई का हकदार है, लेकिन एक बार वयस्क होने के बाद पुत्र स्वयं अपने अधिकार में भूस्वामी है, तो वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में अधिनियम के तहत अनुमेय क्षेत्र रखने का हकदार है और उसे एक परिवार के लिए अनुमेय सीमा तक अलग इकाई रखने तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

5. इसके विपरीत, हिमाचल प्रदेश राज्य ने अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (6) पर बहुत अधिक भरोसा किया और तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 के परिवार के सदस्य हैं, और इसलिए, उनके अनुमेय क्षेत्र

की गणना के प्रयोजनों के लिए उन सभी द्वारा धारित भूमि के साथ-साथ व्यक्तिगत जोत को भी ध्यान में रखा जाएगा।

6. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें कलेक्टर लैंड सीलिंग, ऊना को मूल रिट याचिकाकर्ता संख्या 1 से 5 के अनुमेय क्षेत्र को व्यक्तिगत रूप से आक्षेपित निर्णय में की गई टिप्पणियों के प्रकाश में निर्धारित करने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "23. अनुलग्नक पी-11 में आया है कि याचिकाकर्ता नंबर 1 देव राज के चार बेटे हैं जो सभी बालिग हैं और अपने पिता से अलग रहते हैं। इस साक्ष्य के विपरीत, उत्तरदाताओं ने यह साबित नहीं किया है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 ने नियत तिथि 24.1.1971 से पहले याचिकाकर्ता संख्या 1 के माध्यम से कोई भूमि अर्जित की है। उत्तरदाताओं का साधारण मामला यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 से 5 याचिकाकर्ता संख्या 1 के परिवार के सदस्य हैं, इसलिए, उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी को एक इकाई के रूप में परिवार के सभी सदस्यों के अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के लिए गिना जाएगा और इसलिए, सभी उनमें से सामूहिक रूप से केवल दो इकाइयों के हकदार हैं। उत्तरदाताओं के इस तर्क में कोई बल नहीं है; प्रथमतः, याचिकाकर्ता नंबर 2 पत्नी है और याचिकाकर्ता नंबर 2 से 5 याचिकाकर्ता नंबर 1 के वयस्क बेटे हैं। परिवार में पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चों या उनमें से किसी एक या अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है। याचिकाकर्ता नंबर 2, याचिकाकर्ता नंबर 1

की पत्नी होने के नाते राज कुमार राजिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में उसके लिए उपलब्ध अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने की हकदार है। परिवार की परिभाषा के अनुसार याचिकाकर्ता संख्या 3 से 5 याचिकाकर्ता संख्या 1 के परिवार के सदस्य नहीं हैं और अन्यथा उनकी व्यक्तिगत भूमि हिस्सेदारी को याचिकाकर्ता संख्या के साथ अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के लिए धारा 4 की उप-धारा (6) के तहत नहीं गिना जा सकता है। भले ही नियत तिथि पर याचिकाकर्ता संख्या 3 से 5 नाबालिग थे, फिर भी याचिकाकर्ता संख्या 1 देव राज के अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी की गणना नहीं की जा सकती। सभी याचिकाकर्ताओं का अनुमेय क्षेत्र अधिनियम की धारा 4 के तहत अलग से निर्धारित किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा तय किए गए मेहर अली के मामले को लागू करके दिनांक 22.7.1976 अनुबंध पी-11 के आदेश की समीक्षा करने में गलती की है।"

7. उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए, हिमाचल प्रदेश राज्य और उसके राजस्व अधिकारियों ने विधि का सवाल उठाते हुए विशेष अनुमति द्वारा तत्काल अपील को प्राथमिकता दी है कि क्या हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972, के प्रावधानों के मद्देनजर, एक परिवार पति, पत्नी, एक वयस्क पुत्र और तीन अवयस्क बच्चों में से, यद्यपि 24 जनवरी 1971 को सभी के पास भूमि थी, क्या वे अनुमेय क्षेत्र की दो इकाइयों से अधिक रख सकते थे?

8. उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ एएजी श्री सुर्यनारायण सिंह ने मुख्य रूप से इस आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले का विरोध किया कि हिमाचल प्रदेश भूमि जोत सीमा अधिनियम, 1972 के प्रावधान (संक्षेप में, “अधिनियम”) की व्याख्या इस तरह से की गई है कि इसने सीलिंग कानून के मूल उद्देश्य को ही भटका दिया है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, मूल रिट याचिकाकर्ता देव राज और उनकी पत्नी के 4 बेटे थे; सीलिंग अधिनियम लागू होने के नियत दिन यानी 24.01.1971 को एक बालिग और 3 नाबालिग। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 4 और शब्दों की परिभाषा, "भूस्वामी", "अनुमेय क्षेत्र", "व्यक्ति", " पृथक इकाई" और "अधिशेष क्षेत्र" की सही व्याख्या नहीं की है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि उच्च न्यायालय ने राज कुमार राजिंदर सिंह के मामले में पहले के फैसले को मानने में कानूनी गलती की है, अदालत ने फैसले के पैराग्राफ 19 में एक निष्कर्ष दर्ज किया है, जबकि यह एक तथ्य का मामला था। मामले में श्री सुर्यनारायण ने आगे कहा कि यह दोनों पक्षों का स्वीकृत मामला है कि 24 जनवरी 1971 को भूस्वामी देव राज के परिवार में उनकी पत्नी, एक वयस्क पुत्र और 3 नाबालिग पुत्र थे अधिनियम के प्रावधानों की सही व्याख्या करके, यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि परिवार के सभी सदस्यों के पास अलग-अलग भूमि होगी और अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के लिए उनकी जोत की गणना नहीं की जा सकती है।

9. इसके विपरीत, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल सचथे ने राज कुमार राजिंदर के मामले (एआईआर 1976 एचपी 82 (एफबी) में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर पूरी तरह भरोसा किया। विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पूर्ण पीठ ने अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और माना कि

अतिरिक्त क्षेत्र को इस कल्पना में जोड़ा गया है कि एक वयस्क पुत्र के संबंध में भूमि धारक के हाथ में भूमि स्वामित्व से इतनी अधिक भूमि की आवश्यकता होती है।

10. श्री सचथे ने निवेदन किया कि किसी भी स्थिति में यह कानून का एक स्थापित प्रस्ताव है कि जहां किसी निर्णय को काफी समय तक टिके रहने या पालन करने की अनुमति दी जाती है, तो न्यायालय टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत पर हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक है। इस संबंध में, विद्वान अधिवक्ता ने गजनान और अन्य बनाम सेठ बृंदाबन; (1970) 2 एससीसी 360 और राज नारायण पांडे और अन्य बनाम संत प्रसाद तिवारी और अन्य; (1973) 2 एससीसी 35 के मामले में न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया।

11. इस स्तर पर, हम अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का अध्ययन करना उचित समझते हैं। धारा 3 "परिवार" और "व्यक्ति" शब्द को इस प्रकार परिभाषित करती है:-

> "3(ई) "परिवार" का अर्थ है पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे या उनमें से कोई एक या अधिक;
>
> xxxx
>
> 3(एन) "व्यक्ति" का अर्थ है भूमिमालिक, किरायेदार और कब्जे वाला बंधक, और इसमें एक कंपनी, एक परिवार, एक संघ या व्यक्तियों का अन्य निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, और संपत्ति रखने में सक्षम कोई भी संस्था शामिल है;"

12. उपरोक्त परिभाषाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम में "परिवार" एवं "व्यक्ति" शब्दों का तात्पर्य भूमिस्वामी आदि से है। अधिनियम की धारा 4 इस प्रकार है:-

"धारा 4: अनुमेय क्षेत्र

(1) एक भूमिमालिक या किरायेदार या गिरवीदार का अनुमेय क्षेत्र, जिसके कब्जे में या आंशिक रूप से एक क्षमता में या आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति की क्षमता में या पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों से युक्त परिवार में होगा का सम्मान-

(ए) सुनिश्चित सिंचाई के तहत एक वर्ष में दो फसलें उगाने में सक्षम भूमि- 10 एकड़।

(बी) सुनिश्चित सिंचाई के तहत एक वर्ष में एक फसल उगाने में सक्षम भूमि- 15 एकड़।

(सी) उपरोक्त खंड (ए) और (बी) में वर्णित के अलावा अन्य वर्गों की भूमि, जिसमें बागों के तहत भूमि भी शामिल है- 30 एकड़।

(2) किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिलों, चंबा जिले की तहसील पांगी और उप-तहसील भरमौर, छोटा भंगाल और बड़ा भंगाल के क्षेत्र के लिए उप-धारा (1) के खंड (सी) के प्रयोजनों के लिए अनुमेय क्षेत्र कांगड़ा जिले की पालमपुर तहसील के बैजनाथ कानूनगो सर्कल और शिमला जिले की रोहड़ू तहसील के डोडरा कोवर पटवार सर्कल और रामपुर तहसील के पंद्राबीस परगना का क्षेत्रफल 70 एकड़ होगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत एक परिवार के अनुमेय क्षेत्र को शर्त के अधीन परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त नाबालिग सदस्य के लिए उप-धारा (1) और (2) के तहत अनुमेय क्षेत्र के पांचवें हिस्से से बढ़ाया जाएगा कि कुल अनुमेय क्षेत्र उपधारा (1) और (2) के तहत परिवार के अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगा।

(4) किसी व्यक्ति के प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई माना जाएगा और वह उप-धारा (1) और (2) के तहत एक परिवार के लिए अनुमत सीमा तक भूमि

का हकदार होगा, बशर्ते कि कुल भूमि परिवार और अलग-अलग इकाइयों का कुल क्षेत्रफल उक्त उप-धाराओं के तहत अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगा: बशर्ते कि जहां अलग इकाई के पास कोई भूमि हो, उस इकाई के लिए अनुमेय क्षेत्र की गणना के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा।

(5) यदि किसी व्यक्ति के पास धारा में वर्णित दो या दो से अधिक श्रेणियों की भूमि है इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के (ए), (बी) और (सी) के बाद अनुमेय क्षेत्र निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया जाएगा: -

(i) इस धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित क्षेत्रों में, उपधारा (1) के खंड (ए) में उल्लिखित एक एकड़ भूमि को खंड (बी) में उल्लिखित डेढ़ एकड़ भूमि के रूप में गिना जाएगा। उपधारा (1) और उपधारा (1) के खंड (सी) में उल्लिखित सात एकड़ भूमि;

(ii) इस धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में, उपधारा (1) के खंड (ए) में उल्लिखित एक एकड़ भूमि को उल्लिखित डेढ़ एकड़ भूमि के रूप में गिना जाएगा। उपधारा (1) के खंड (बी) में, और उपधारा (1) के खंड (सी) में उल्लिखित तीन एकड़ भूमि:

बशर्ते कि खंड (i) और (ii) में निर्धारित अनुपात के आधार पर, अनुमेय क्षेत्र को उपधारा (2) और उपधारा (1) के खंड (सी) में उल्लिखित भूमि की श्रेणी में परिवर्तित किया जाएगा। जैसा भी मामला हो, और खंड के मामले में इस प्रकार परिवर्तित कुल क्षेत्रफल 70 एकड़ से अधिक नहीं होगा (i) और खंड (ii) के मामले में 30 एकड़।

(6) जहां कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य है, ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि को अनुमेय क्षेत्र की गणना के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा।''

13. धारा 4 की सरल भाषा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी एक परिवार हो सकता है, जो संपत्ति रखने में सक्षम हो, जिसमें पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चे शामिल हों। धारा 4 की उपधारा (1) के अनुसार, पति, पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों वाले परिवार का अनुमेय क्षेत्र उसमें दी गई सीमा तक होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 4(1) के तहत, परिवार नाबालिग बच्चों की संख्या के संदर्भ में सीमित है, हालांकि परिभाषा खंड में, यानी धारा 3(ई) के तहत, "परिवार" नाबालिग बच्चों के संदर्भ में सीमित नहीं है। इसलिए अधिनियम के तहत अनुमत क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से परिवार को एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में लिया जाएगा। हालाँकि, धारा 4 की उपधारा (4) यह स्पष्ट करती है कि प्रत्येक वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई माना जाएगा और वह उपधारा (1) के तहत एक परिवार के लिए स्वीकार्य सीमा तक भूमि का हकदार होगा। (2) इस शर्त के अधीन कि परिवार की कुल भूमि और अलग-अलग इकाइयों की कुल भूमि उक्त उप-धारा के तहत अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगी। धारा 4 की उपधारा (6) यह स्पष्ट करती है कि जहां कोई व्यक्ति परिवार का सदस्य है, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित भूमि के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों द्वारा धारित भूमि अनुमेय क्षेत्र की गणना करने के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाएगा।

14. दूसरे शब्दों में, धारा 4 के संपूर्ण प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 4 की उपधारा (6) को पढ़ने से, यह स्पष्ट हो जाता है कि भले ही प्रतिवादी एक व्यक्ति के रूप में अपनी-अपनी व्यक्तिगत क्षमता में संपत्ति धारण कर रहे हों, भूमि उनके पास है अनुमेय क्षेत्र की गणना के प्रयोजन के लिए उन्हें ध्यान में रखा जाएगा। यह प्रावधान अपने स्पष्ट शब्दों में किसी व्यक्ति के वयस्क पुत्र के मामले में एक प्रकार का अपवाद प्रदान करता है। उस स्थिति में ऐसे वयस्क पुत्र को एक अलग इकाई के रूप में माना जाएगा और वह परिवार के अनुमेय क्षेत्र की सीमा तक अनुमेय क्षेत्र की अलग इकाई

पाने का हकदार है, बशर्ते कि परिवार की कुल भूमि और एक की कुल भूमि अलग-अलग इकाइयों को एक साथ रखने पर अनुमेय क्षेत्रफल के दोगुने से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम उपधारा (4) को सूक्ष्मता से पढ़ें तो पता चलता है कि पहले भाग में विधायिका ने "पृथक इकाई" शब्द का प्रयोग किया है लेकिन बाद के भाग में विधायिका ने "पृथक इकाई" शब्द का बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है। धारा 4 की उप-धारा (4) के शुरुआती शब्द, "किसी व्यक्ति के प्रत्येक वयस्क पुत्र" से शुरू होते हैं, जिसका अर्थ है कि भले ही किसी व्यक्ति के एक से अधिक वयस्क पुत्र हों, सभी को अलग-अलग इकाई के रूप में माना जाएगा, लेकिन शर्त के अधीन। परिवार की कुल भूमि और अलग-अलग इकाइयों की कुल भूमि उक्त उप-धारा के तहत अनुमेय क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं होगी।

15. अधिनियम की धारा 6 इस प्रकार है:-

> “6. भूमि की अधिकतम सीमा:- किसी भी कानून, रूढि, प्रथा या समझौते में निहित किसी भी विपरीत बात के बावजूद, कोई भी व्यक्ति भूस्वामी या किरायेदार या गिरवीदार के रूप में कब्जा करने का हकदार नहीं होगा या आंशिक रूप से एक क्षमता में और आंशिक रूप से किसी अन्य क्षमता में, नियत दिन पर या उसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य के भीतर अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि।"

16. एक अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान धारा 17 है, जो भविष्य में विरासत द्वारा या अन्यथा अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि के अधिग्रहण या इस अधिनियम के संचालन के परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्र में वृद्धि के मामले से संबंधित है। धारा 17 इस प्रकार है:-

"धारा 17: भविष्य में विरासत द्वारा या अन्यथा अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का अधिग्रहण या इस अधिनियम के संचालन के परिणामस्वरूप ऐसे क्षेत्र में वृद्धि:

(1) धारा 15 के प्रावधानों के अधीन, यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भूमि मालिक या किरायेदार के रूप में हो, किसी ऐसे व्यक्ति से विरासत में या वसीयत या उपहार द्वारा प्राप्त करता है, जिसका वह उत्तराधिकारी है, या किसी व्यक्ति के पास है किसी भी भूमि को हस्तांतरण, विनिमय, पट्टे, समझौते या निपटान द्वारा अर्जित किया गया है, या यदि, इस तरह के प्रारंभ के बाद, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य तरीके से किसी भी भूमि का अधिग्रहण करता है, जो पहले से ही स्वामित्व वाली या उसके द्वारा रखी गई भूमि के साथ या उसके बिना, कुल मिलाकर अधिक है अनुमेय क्षेत्र या कोई व्यक्ति जिसकी भूमि इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के संचालन के परिणामस्वरूप अनुमेय क्षेत्र से अधिक है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर, कलेक्टर को निर्धारित प्रपत्र और तरीके से विवरण प्रस्तुत करेगा। सभी भूमि और कुल मिलाकर उस स्वीकार्य क्षेत्र से अधिक भूमि का चयन नहीं करना चाहिए जिसे वह अपने पास रखना चाहता है, और यदि ऐसे व्यक्ति की भूमि एक से अधिक पटवार सर्कल में स्थित है, तो उसे धारा 9 द्वारा अपेक्षित घोषणा भी प्रस्तुत करनी होगी।

(2) यदि वह रिटर्न प्रस्तुत करने और निर्धारित अवधि के भीतर अपनी भूमि का चयन करने में विफल रहता है, तो कलेक्टर उसके

संबंध में रिटर्न में दर्शाई जाने वाली आवश्यक जानकारी ऐसी एजेंसी के माध्यम से प्राप्त कर सकता है जिसे वह उचित समझे और उसके लिए भूमि का चयन कर सकता है। धारा 8 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तरीके से।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति घोषणा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो (धारा 9) लागू होगा.

(4) ऐसे व्यक्ति की अतिरिक्त भूमि धारा 15 के तहत अधिशेष क्षेत्र के रूप में उपयोग के लिए या ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए राज्य सरकार के निपटान में होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है।

स्पष्टीकरण:- परिवार के मामले में, रिटर्न परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है और एकमात्र नाबालिग के मामले में उसके अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है:

बशर्ते कि कलेक्टर, अधिशेष क्षेत्र का निर्धारण करने से पहले, परिवार के सभी सदस्यों को सुनवाई का अवसर देगा।"

17. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि जब कोई व्यक्ति/जमींदार अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद अनुमेय क्षेत्र से अधिक भूमि का अधिग्रहण या उत्तराधिकार करता है, तो ऐसे भूमि धारक को हिमाचल के नियम 16 के अनुसार कलेक्टर को अलग से रिटर्न दाखिल करना होगा। प्रदेश भूमि जोत सीमा नियम, 1972.

18. उच्च न्यायालय ने **राजकुमार राजिन्द्र सिंह बनाम भारत संघ**, आईएलआर 1976 एचपी 453 में उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया। उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने पूर्ण के कुछ पैराग्राफ उद्धृत

किए बेंच का फैसला आक्षेपित आदेश की सराहना करने के लिए, हम पैराग्राफ संख्याएँ उद्धृत करेंगे। आक्षेपित निर्णय के 17, 18 और 19 इस प्रकार हैं:-

“17. राजकुमार राजिंदर सिंह के मामले (सुप्रा) में, पैराग्राफ -8 में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने निम्नानुसार व्यवस्था दी है: -

> “.....यह किसी व्यक्ति या परिवार के मामले में अनुमत क्षेत्र है और यह ऐसे व्यक्ति या परिवार की भूमि स्वामित्व के संबंध में अनुमेय क्षेत्र है। यह अकेले ऐसे व्यक्ति या परिवार की भूमि-धारण है जो धारा 4 की विषय-वस्तु बनती है, और कई उप-धाराएँ ऐसी भूमि-धारण के संबंध में अनुमेय क्षेत्र की गणितीय गणना के लिए सिद्धांत निर्धारित करती हैं। धारा 4 का संबंध किसी अन्य व्यक्ति या परिवार की भूमिधरी से नहीं है और न ही एक भूमिधारक के अधिकारों को दूसरे के पक्ष में हस्तांतरित करने से है।"

18. अनुच्छेद 24 में, पूर्ण पीठ ने माना है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 4 की उप-धारा (6) इस बात पर विचार करती है कि जहां एक व्यक्ति परिवार का सदस्य है, ऐसे परिवार के पास मौजूद भूमि के साथ-साथ परिवार के सभी सदस्यों के पास मौजूद भूमि भी शामिल है। अनुमेय क्षेत्र की गणना के प्रयोजनों के लिए परिवार को ध्यान में रखा जाएगा, यह प्रश्न केवल एक परिवार के संबंध में ही उठ सकता है, प्रावधान केवल अनुमेय क्षेत्र की गणितीय गणना से संबंधित है।

19. पैराग्राफ- 19 में, पूर्ण पीठ ने कहा है:-

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जहां एक पति और बच्चों को जमीन रखने का अधिकार है वहीं पत्नी को इस अधिकार से वंचित किया गया है। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। पति, पत्नी और बच्चों से

युक्त एक परिवार को अनुमेय क्षेत्र के निर्धारण के लिए एक इकाई के रूप में मान्यता दी गई है, और परिवार की भूमि स्वामित्व को उस उद्देश्य के लिए माना जाता है। यदि पत्नी अपने अधिकार में अलग से भूमि रखती है, तो वह अपने लिए उपलब्ध अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में माने जाने की हकदार है।

19. पूर्ण पीठ के फैसले के उपरोक्त पैराग्राफों के अवलोकन से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय उक्त अधिनियम की धारा 4 में प्रयुक्त भाषा से पूरी तरह से हट गया है। उच्च न्यायालय ने यह मानकर कानून की गंभीर त्रुटि की है कि यदि पत्नी अपने अधिकार में अलग से जमीन रखती है, तो वह अपने लिए उपलब्ध अनुमेय क्षेत्र का निर्धारण करने के उद्देश्य से एक व्यक्तिगत व्यक्ति के रूप में व्यवहार करने की हकदार है। हमारी निश्चित राय है कि पूर्ण पीठ ने अधिनियम के प्रावधानों की सही व्याख्या नहीं की है।

20. उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई यह तर्क कि आक्षेपित निर्णय में टकटकी निर्णय के सिद्धांत पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। **गजनान** (सुप्रा) के मामले में उत्तरदाताओं द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया, इस न्यायालय ने माना कि न्यायिक निर्णय में निश्चितता बनाए रखने के लिए अदालत को ऐसे निर्णय में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए जो लंबे समय तक कायम रहे। हालाँकि, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है कि यह सिद्धांत "जहां किसी क़ानून का अर्थ अस्पष्ट है और एक से अधिक व्याख्याओं में सक्षम है" लागू होगा।

21. इस न्यायालय ने इंद्रा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, आदि एआईआर (1993) एससी 477 में, फैसले के पैराग्राफ 26-ए में, टकटकी के

निर्णय के सिद्धांत पर विचार किया और देखा कि कानून में निश्चितता, स्थिरता है और निरंतरता अत्यधिक वांछनीय विशेषताएं हैं। जहां कोई निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और उस पर कभी संदेह नहीं किया गया है, हमने उसका सम्मान किया है, जब तक कि निश्चित रूप से, उससे अलग होने के लिए बाध्यकारी और मजबूत कारण न हों।

22. हम यह स्पष्ट करते हैं कि न्यायिक निर्णय में निश्चितता बनाए रखने के लिए हमें उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से बचना होगा जो लंबे समय से स्टेयर डिसिसिस के सिद्धांत पर कायम है। हालाँकि, उक्त सिद्धांत वहां लागू होगा जहां क़ानून का अर्थ अस्पष्ट है और एक से अधिक व्याख्या करने में सक्षम है। मौजूदा मामले में, अधिनियम/क़ानून का प्रावधान बहुत स्पष्ट है और इसलिए, टकटकी निर्णय लेने का सिद्धांत उत्तरदाताओं के लिए कोई मदद नहीं करता है।

23. इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है कि तत्काल मामला 1974 में शुरू की गई कुछ कार्यवाहियों से उत्पन्न हुआ और इस न्यायालय तक पहुंचा। पूर्ण पीठ का फैसला वर्ष 1976 में ही आया था और इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, वर्तमान मामले के तथ्यों में घूरने का निर्णय का सिद्धांत लागू नहीं होना चाहिए।

24. मामले के संपूर्ण तथ्यों और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार करते हुए, हमारी निश्चित राय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून, रिकॉर्ड पर तथ्यों के विपरीत है, और उसमें दर्ज निष्कर्षों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

25. इसलिए, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित फैसले को रद्द करते हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **श्री प्रदीप कुमार मोदी** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।